[2009] 6 एस. सी. आर. 142

राजस्थान राज्य

बनाम

मोहन लाल और अन्य

(आपराधिक अपील सं. 822/2003)

15 अप्रैल, 2009

[डॉ. अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा.302-उच्च न्यायालय सी द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ अपील-उच्च न्यायालय ने इस आधार पर बरी करने का निर्देश दिया कि चश्मदीद गवाहों का सबूत विश्वसनीय नहीं था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःउच्च न्यायालय का दृष्टिकोण प्रशंसनीय था, इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया-चश्मदीद गवाहों का आचरण अप्राकृतिक था-मौके पर उनकी उपस्थिति भी संदिग्ध थी-साथ ही जांच के दौरान दिए गए और अदालत में दिए गए उनके बयान में भिन्नता थी।

उत्तरदाताओं को दोषी ठहराया गया था। आई. पी. सी. 302 सपठित 34 । उच्च न्यायालय ने पाया कि चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे और बरी करने का आदेश दिया। इसलिए अपील दायर की गई है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अवधारित किया; कथित चश्मदीद गवाह का आचरण बिल्कुल अप्राकृतिक था।सभी मामलों में व्यक्तियों का आचरण एफ निर्धारक नहीं होगा, यह कई कारकों पर निर्भर करेगा।घटना के गवाह होने का दावा करने वाले चार व्यक्तियों ने मृतक को आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए हमलों से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया।पीडब्लू1 मृतक का बेटा था।उच्च न्यायालय ने देखा कि तथाकथित चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति व्यावहारिक रूप से स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि जांच के दौरान और अदालत में दिए गए बयानों में विभिन्न भिन्नताएं थीं।उच्च न्यायालय ने पाया कि यह आचरण न केवल अप्राकृतिक था, बल्कि यह साबित किया कि घटना के स्थान पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध है।उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।[पैरा 5,6 और 7] [144-डी-जी]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील संख्या 822/2003

1997 के डी. बी. आपराधिक अपील सं. 71 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर के दिनांकित 30-07 2002 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से मनीष सिंघवी, ए. ए. जी. और मिलिंद कुमार।

प्रतिवादी के लिए एस. आर. बाजवा, पुनीत जैन, अर्चना तिवारी, सुशील कुमार जैन और प्रतिभा जैन।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, न्यायमूर्ति

1.अपीलार्थी-राज्य के लिए विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. इस अपील में चुनौती राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ की एक खंड पीठ के फैसले को दी गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराध के कथित आरोप के लिए मुकदमे का सामना करने वाले प्रतिवादियों को बरी करने का निर्देश दिया गया है। मूल रूप से पाँच व्यक्तियों को मुकदमे का सामना करना पड़ा और उनमें से दो आरोपी व्यक्तियों मोती राम और रामजी लाल को विद्वान सत्र न्यायाधीश झुनझुनू के फैसले से बरी कर दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित निर्णय द्वारा, वर्तमान प्रतिवादियों को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया।

3. अभियोजन पक्ष ने संक्षेप में कहा कि बालूसिंह (इसके बाद मृतक के रूप में संदर्भित) पर वर्तमान प्रतिवादियों और दो बरी किए गए अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था और इस प्रक्रिया में बालू सिंह ने अपनी जान गंवा दी थी।जानकारी मदन सिंह यादव (पीडब्लू 9) द्वारा दर्ज कराई गई थी जो मृतक के बेटे थे।जाँच के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया और चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों ने निर्दोष होने का अनुरोध किया, इसलिए मुकदमा चलाया गया। आयोजित किया गया था।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान उत्तरदाताओं को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया। दोषी व्यक्ति ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की, जिसने जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उन्हें बरी करने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय ने तथाकथित चश्मदीद गवाह पीडब्लू1,2,5 और 9 के साक्ष्य को विश्वसनीय और ठोस नहीं पाया और इसलिए बरी करने का निर्देश दिया।

4. अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने कहा कि चूंकि चार चश्मदीद गवाह थे, इसलिए साक्ष्य को सीधे बरी करने के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।प्रत्यर्थी के विद्वान के वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है और चश्मदीद गवाह के साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद इस पर पहुंचा गया है।

5. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि तथाकथित चश्मदीद गवाह का आचरण बिल्कुल अप्राकृतिक था। उन्होंने मृतक को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जब उस पर हमला किया जा रहा था या जब आरोपी व्यक्ति कथित रूप से मृतक के शव को ले गए थे।

6.हालाँकि सभी मामलों में व्यक्तियों का आचरण निर्धारिक नहीं होगा, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करेगा।वर्तमान मामले में निस्संदेह घटना के गवाह होने का दावा करने वाले चार व्यक्तियों ने मृतक को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए गए हमलों से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया।एफ पीडब्लू1 मृतक का बेटा

था।उच्च न्यायालय ने देखा कि तथाकथित चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति व्यावहारिक रूप से स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि जांच के दौरान और अदालत में दिए गए बयान में विभिन्न भिन्नताएं थीं।

7. उच्च न्यायालय ने पाया कि आचरण न केवल अप्राकृतिक था, बल्कि यह भी साबित किया कि घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध थी।उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण प्रशंसनीय है, हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज कर दी गई ।